

भारत में खाद्य समस्या के समाधान के उपाय

(Reduction of food problem in India)

देश की खाद्य-समस्या के निराकरण के लिए निम्नांकित कुछ सुझाव:-

(क) खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि (Increase in production of foodgrains)-

खाद्य-समस्या के समाधान के लिए सर्वप्रथम तो खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि अनिवार्य है जिसके लिए निम्नांकित तरीकों को अपनाना आवश्यक है-

1. वैज्ञानिक तरीकों के प्रयोग के द्वारा कृषि की उपज में वृद्धि- भारतीय कृषि की प्रति एकड़ उपज में वैज्ञानिक तरीकों के प्रयोग द्वारा पर्याप्त वृद्धि की जा सकती है; 20% उचित खाद्य के प्रयोग द्वारा एवं 5% उत्तम बीजों के प्रयोग तथा 15% कीड़े-मकौड़े से फसलों की रक्षा द्वारा। चावल एवं गेहूँ की उपज में तो यह सम्भावना क्रमशः 50 तथा 100% की है। जापानी पद्धति से धान तथा मैक्सिको पद्धति से गेहूँ की खेती द्वारा भी प्रति हेक्टर उपज में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है जिससे यह सम्भावना सत्य ही जान पड़ती है। देश में सम्पूर्ण खाद्यान्नों की उत्पादन 1940-50 में 550 लाख टन से बढ़कर 1995-96 में 1850 लाख टन हो गया, यानी इसमें उगुणा से भी अधिक वृद्धि सम्भव है।

11/07/20

2. भूमि-सुधार की व्यवस्था- भारत की वर्तमान भूमि व्यवस्था के अंतर्गत कृषि कार्य में लगे हुए अधिकांश व्यक्ति भूमिहीन मजदूर हैं जिनमें कृषि में सुधार के लिए उत्साह प्रायः का अभाव पाया जाता है। साथ ही, हमारे यहाँ जोते-इन्नी छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित हैं कि उनमें सफलतापूर्वक कृषि-कार्य भी सम्पन्न नहीं हो सकता। सहकारी कृषि-व्यवस्था के द्वारा इनके अकार में वृद्धि आवश्यक है जिससे वैज्ञानिक ढंग पर कृषि कार्य सम्भव हो सके।

3. कृषि-क्षेत्र का विस्तार - देश में खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि का एक तरीका कृषि की जानेवाली भूमि के क्षेत्र में विस्तार भी है। इसके लिए बंजर तथा बेकार भूमि के पुनरुद्धार द्वारा इन्हें कृषि योग्य बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। भूमि के उपयोग सम्बन्धी उपलब्ध आँकड़ों के

अनुसार देश में 600 लाख एकड़ कृषि-योग्य बेकार भूमि हैं, जिनका सुधार कर कृषि योग्य बनाया जा सकता है। ऐसी भूमि का आबाद होने से देश की खाद्य-समस्या का बहुत कुछ समाधान किया जा सकता है। परन्तु, पुनरुद्धार के साथ-साथ इनमें कृषि के लिए अन्य सुविधाओं जैसे सिंचाई, खाद तथा यातायात वगैरह की भी व्यवस्था करनी होगी। यदि सच पूछा जाय तो देश में अब कृषि क्षेत्र के विकास की बहुत ही कम संभावना है। इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय कृषि का भविष्य गहन कृषि का कि विस्तृत कृषि पर निर्भर करता है।

1. संस्थागत परिवर्तन (Institutional changes) - संस्थागत परिवर्तनों द्वारा खाद्यान्नों के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि की जा सकती है। यद्यपि कुछ विचारकों जैसे प्रो. लीवीस (Lewis) ने कृषि-उत्पादन में वृद्धि के सिलसिले में भूमि-सुधार के महत्व को स्वीकार नहीं किया है यद्यपि यह कहा जा सकता है कि जातों की पकवन्दी तथा अधिकतम सीमा के निर्धारण से इसमें अत्यधिक सीमा के सहायता मिलेगी।

(ख) खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था में सुधार (Changes in the System of Distribution of food grains) - खाद्य-समस्या के समाधान के लिए खाद्यान्नों के वितरण की व्यवस्था में सुधार भी अनिवार्य है। पिछले कुछ वर्षों से सरकार इस सम्बन्ध में विभिन्न उपयोजनों को अपनाया है। किन्तु, इन व्यापारों की सफलता, खाद्य प्रशासन की कुशलता पर निर्भर करती है। वास्तव में, खाद्य-समस्या के निराकरण के लिए देश की खाद्य-प्रशासन व्यवस्था के दोषों को दूर करना भी आवश्यक है। भारत में खाद्य-समस्या की जटिलता खाद्य-व्यवस्था के कर्मचारियों की अकुशलता तथा वैईमानी एवं वीषयुक्त खाद्य-व्यवस्था की वजह है। इसमें सुधार अनिवार्य है। जब तक देश की खाद्य-व्यवस्था में आवश्यक सुधार नहीं लाया जायगा तब तक खाद्यान्न के उत्पादन की कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती।

(ग) खाद्यान्नों के मूल्य को स्थायित्व कर प्रदान करना (Measures to stabilize food grains prices) - वर्तमान समय में किसानों को अधिक अन्न उपजाने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए उद्देश्य से सरकार प्रतिवर्ष प्राश्मन में ही महत्वपूर्ण खाद्यान्न के लिए न्यूनतम मूल्य धीषित करती है। यदि बाजार में किसी अन्न की कीमत धीषित मूल्य से नीचे आ जाय तो

सरकार, उक्त मूल्य में इसे खरीदने के लिए तैयार रहती है। सरकार की खाद्यान्न नीति का प्रधान उद्देश्य खाद्यान्नों का मूल्य का दृष्टांत है। इस उद्देश्य से सरकार द्वारा विदेशों से आवश्यकतानुसार खाद्यान्नों का आयात भी किया जाता है एवं उचित मूल्य को दुकानों (Fair Price Shops) द्वारा खाद्यान्नों के वितरण की व्यवस्था भी की जाती है; अतः सरकार ने मूल्य-निर्धारित की है और एक "Agricultural Price Commission" की नियुक्ति भी की है जो सरकार को मूल्य के सम्बन्ध में सलाह देते रहता है।

### (घ) अन्य उपाय (Other measures)-

1. जनसंख्या का नियोजन (Population Planning) - भारत की खाद्य-समस्या के लिए जनसंख्या का नियंत्रण भी आवश्यक है। 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या में प्रायः प्रतिवर्ष 1.80 करोड़ से भी अधिक की दर से वृद्धि होती है जिससे खाद्य-समस्या का कोई स्याबी हल नहीं मिल सकता। "कम बच्चे और उत्पन्न करो" आन्दोलन के अतिरिक्त इस स्थिति में किसी प्रकार से भी अधिक जन उपजाऊ आन्दोलन सफल नहीं हो सकता। (Grow more food campaign cannot be successful without Grow less children campaign) अतः जनसंख्या के नियोजन को खाद्य-नियोजन का एक आवश्यक अंग समझकर देश में परिवर्तन परिवार नियोजन का अधिकाधिक प्रचार अनिवार्य है।

2. गाय, भैंस तथा मुर्गी आदि की संख्या में वृद्धि - हमारे भोजन में पौष्टिक तत्वों का अभाव है, उसे अधिक संख्या में गाय, भैंस तथा मुर्गी आदि को पाल कर भी दूर किया जा सकता है। ऐसा करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। इससे दुग्ध, धी तथा अण्डों की पूर्ति बढ़ेगी जिससे इसका अधिकाधिक प्रयोग होगा।

3. भोजन की वर्तमान आदतों में परिवर्तन - उपरोक्त सभी उपायों के साथ-साथ भोजन की वर्तमान आदतों में परिवर्तन की भी आवश्यकता है। अभी तक हमारे देश के भोज्य-पदार्थों में अन्न की ही प्रधानता रही है, लेकिन अन्न की प्रधानता को भाग-सराजी के अधिक प्रयोग द्वारा कम

करना चाहिए। इसके साथ ही चावल के बदले जेठू के उपयोग में  
 पृथ्वी की प्रचल आवश्यकता है। वास्तव में, भोजन में फल, आग-सहजी,  
 मखली आदि के अद्वितीय प्रयोग द्वारा अन्न की मात्रा को कम किया जा  
 सकता है।

(अनुसंधानकर्ता) पापु-गढ़ (1)